



दैनिक

www.dainikdevvrat.in

देवव्रत

आजमगढ़, उ.प्र.
वर्ष 36, अंक 294
पृष्ठ 08, मूल्य 3.00
22 जुलाई 2026, बुधवार

लखनऊ, नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र (राबर्टसगंज, अनपरा, शक्तिनगर), सिंगरौली, मिर्जापुर, अयोध्या, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, अम्बेडकरनगर एवं आजमगढ़ से प्रसारित

E-mail : dainikdevvrat@gmail.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

1

राहुल-अखिलेश की गिरफ्तारी से सियासी भूचाल, देर रात रिहा

पीएम आवास पर धरना देते नेता विपक्ष को गिरफ्तारी के दौरान लगी नाक में चोट, निकला खून

कांग्रेस सांसदों के साथ प्रियंका गांधी भी हिरासत में

नई दिल्ली, 21 जुलाई (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। प्रधानमंत्री आवास के बाहर छात्रों

लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार अब विपक्ष की आवाज

प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। जब पुलिस उन्हें हटाने पहुंची तो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखा। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़कर घसीटते हुए उठाया और हिरासत में ले लिया। इसी दौरान उनकी नाक पर चोट लगी और खून बहने लगा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, केरल के वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन सहित अनेक सांसदों और नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा, सरकार डरपोक है। वह हमसे डरती है, हम उससे नहीं डरते। पुलिस बस में चढ़ाए जाते समय उनका विरोध भी पूरे घटनाक्रम का प्रमुख दृश्य बन गया।

राहुल गांधी ने प्रदर्शन से पहले कहा था कि सरकार छात्रों पर हुई कथित पुलिस बर्बरता का जवाब देने से भाग रही है और संसद में चर्चा कराने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग दोहराई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब देश का नेता प्रतिपक्ष भी शांतिपूर्ण धरना देने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसे घसीटकर उठाया जाता है, तो आम नागरिकों के अधिकारों की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। पार्टी ने कहा कि यह केवल राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक असहमति पर बलपूर्वक कार्रवाई का उदाहरण है।

इस दौरान पंजाब कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई सांसदों और कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की काली तस्वीर बताते हुए संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने का ऐलान किया। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास उच्च सुरक्षा क्षेत्र है और निषेधाज्ञा लागू होने के कारण प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया गया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने के बजाय पुलिस के बल पर विरोध की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।



के समर्थन में धरने पर बैठे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने जबरन घसीटकर हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान हुई धक्का-मुक्की में राहुल गांधी की नाक पर चोट लग गई और खून बहने लगा। घटना की तस्वीरें सामने आते ही देश की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इसे

को बल प्रयोग से कुचलने पर उतर आई है। संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस सांसदों और नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालकर सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी

कांग्रेस की गुप्त योजना : अचानक PM आवास के बाहर जुट गए सभी सांसद

नई दिल्ली, 21 जुलाई (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकालने की कोशिश और इस दौरान पुलिस-प्रशासन की तरफ से छात्रों पर हुए बल-प्रयोग ने अब विपक्षी दलों को भी सरकार के खिलाफ सक्रिय कर दिया है। कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसद मंगलवार को एकाएक ही प्रधानमंत्री के दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास के बाहर जुट गए और धरना शुरू कर दिया। विपक्ष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस धरने के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह,

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन



ने राहुल गांधी समेत सभी प्रदर्शन सांसदों और नेताओं को धरना खत्म करने के लिए समझाने की कोशिश की। हालांकि, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, राहुल ने धरनास्थल से हटने से इनकार कर दिया है। राहुल ने देशवासियों से धरने में शामिल होने की अपील भी कर दी। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर कांग्रेस के सांसद अचानक से संसद सत्र के बीच प्रधानमंत्री आवास के बाहर कैसे जुट गए और धरना शुरू कर दिया। धरने में कौन-कौन शामिल है।

कर्नाटक-केरल के सीएम सहित कांग्रेस के सांसद हिरासत में लिये गये

नई दिल्ली, 21 जुलाई (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा और मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में मंगलवार (21 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हो रहे इस प्रदर्शन में दो मौजूदा मुख्यमंत्री दुर्गा कर्नाटक के डीके शिवकुमार और केरल के वीडी सतीशन भी मौजूद हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस सांसदों और नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर पैदल मार्च किया। वे मोदी सरकार की कथित युवा-विरोधी नीतियों और सोमवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर की गई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'हम कल छात्रों के साथ हुई बर्बरता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगने के लिए उनके आवास तक मार्च करके पहुंचे हैं सरकार न तो इस मामले में कोई जवाबदेही लेना चाहती है और न ही इस पर संसद में बहस करना चाहती है। उन्होंने आगे जोड़ा, 'भारत के युवाओं का



भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री 'इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के बाहर प्रदर्शन कर रहे कुछ सांसदों और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए नेताओं में पंजाब कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल थे। उन्होंने छात्रों की चिंताओं पर बात करने से इनकार करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 'आतंक जैसी हथकंडे' अपनाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, 'यह गुंडागर्दी है। अगर सांसदों के साथ ऐसा बातव किया जाएगा, तो छात्रों का क्या होगा।

‘कहां ले जा रहे हो, पुलिस भाई’

अखिलेश का सवाल बना चर्चा का विषय

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की खबर से दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब

नई दिल्ली, 21 जुलाई (एजेंसी/ देवव्रत संवाद)। प्रधानमंत्री आवास के बाहर छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी विपक्ष के साथ धरने में शामिल हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड़ा और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटाया। हिरासत के दौरान पुलिस वाहन में बैठे अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वह मुस्कुराते हुए पुलिसकर्मियों से पूछते नजर आ रहे हैं। कहां ले जा रहे हो, पुलिस भाई।

संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च कर छात्रों के मुद्दे, कथित पेपर लीक मामलों और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी धरनास्थल पर पहुंच गए, जिससे विपक्ष का प्रदर्शन और मुखर हो गया। स्थिति तनावपूर्ण होने पर दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई सांसदों और नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन से संसद मार्ग थाने ले जाया गया।

हिरासत के दौरान सामने आए वीडियो में अखिलेश यादव पुलिसकर्मियों से सहज अंदाज में पूछते हैं, कहां ले जा रहे हो, पुलिस भाई। उनका यह संवाद और मुस्कुराता हुआ चेहरा सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया। समर्थकों ने इसे विपरीत परिस्थितियों में भी उनके शांत और संयमित व्यवहार के रूप में साझा किया। हिरासत में लिए जाने से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों की मांगों पर ध्यान दें। सरकार संवाद से क्यों बच रही है। उन्होंने दोहराया कि समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रही है। उधर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास उच्च सुरक्षा क्षेत्र होने

के कारण निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर

की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही पूरा सियासी



प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं की हिरासत के बाद यह मुद्दा संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव

बवडर खड़ा हो गया, जहां दिल्ली की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों समाजवादी पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों सहित कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में सपा के पूर्व मंत्री और विधायक अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे

आजमगढ़, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने

वक्ताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी युवाओं, छात्रों और

लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने की मांग की। अंबेडकर पार्क में देर शाम शुरू हुआ यह



लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। नेताओं ने केंद्र सरकार से विपक्षी नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने तथा

विरोध धरना देर रात तक जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अखिलेश यादव की रिहाई की मांग करते हुए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

‘देवव्रत’ हिन्दी दैनिक

‘नहीं मरी आवाज’

हिटलरशाही तर्ज पर,
खुलकर नाचा राज ।
फिर भी धरना ना मरा,
नहीं मरी आवाज ।
श्रेष्ठ भावी भारत की ।

दो टूक - धीरू भाई
22 जुलाई 2026

C
M
Y
K

खेल आयोजनों में राजनीतिक हस्तक्षेप हमेशा उन्हें विवादित बनाते हैं

आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन के हाथों पिछले चैंपियन अर्जेंटीना की हार के साथ ही दुनियाभर में छाया फुटबॉल का खुमार थम गया।निस्संदेह, यह फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वकप था। संभवतः हाल के दशकों में संपन्न विश्वकप मुकाबलों में सबसे अधिक विवादास्पद भी। इस आयोजन को सफल बनाने में तीन मेजबान देशों—अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की भागीदारी रही है। इस टूर्नामेंट में 48 टीमों ने शिरकत की और 1०4 मैचों का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता को तो दिखाया ही, साथ ही इस खेल के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए। बहरहाल, स्पेन ने 16 साल बाद अपना यह दूसरा खिताब जीता। उसने एक औसत दर्जे के फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-० से हराया। वहीं दूसरी ओर तीसरे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला टूर्नामेंट की दो सबसे शानदार टीमों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। इस बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबले में इंग्लैंड ने 6-4 से जीत हासिल की। वहीं इस टूर्नामेंट में कुछ अल्प ज्ञात टीमों का प्रदर्शन फुटबॉल की दुनिया में उम्मीद जगाने वाला रहा। इस विश्व कप में कैप वर्डे, डेमोक्रैटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कुराकाओ जैसे छोटे देशों का प्रेरणादायक खेल दर्शकों

को मंत्रमुग्ध कर गया। बहरहाल, एक बार फिर किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी जैसे फुटबॉल के बड़े सितारों ने इस सबसे बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरी। दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक बार फिर कहानी निराशाजनक रही। उनके प्रशंसक उनकी यादगार विदाई चाहते थे। लेकिन किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी में टीम वर्क की बड़ी भूमिका होती है। खिलाड़ियों की साझी भूमिका से ही बड़े स्टार खिलाड़ी चमक सकते हैं। यही वजह है कि किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी जैसे अद्भुत खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद विश्वकप खिताब से वंचित रह गए। निस्संदेह, किसी भी मजबूत टीम के नगीनों के साझे प्रयास ही ही स्वर्णिम सफलता का निर्धारण होता पाता है।बहरहाल, अब तक के सबसे बड़े और तीन देशों में खेले गए इस टूर्नामेंट के साथ कई तरह के विवाद भी जुड़े। टेकोनोर्लांजी पर फीफा की बढ़ती निर्भरता को लेकर भी आलोचकों ने सवाल उठाये। विशेष रूप से वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी वीएआर सिस्टम को लेकर संशय पैदा हुआ। फुटबॉल प्रेमियों ने माना कि यह सिस्टम भरोसेमंद नहीं है। इसके उपयोग और भूमिका को लेकर कई खिलाड़ियों, कोचों और दर्शकों में नाराजगी देखी गई। वहीं दूसरी ओर अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक को लेकर भी काफी हंगामा देखने में आया।

दरअसल, ये अमेरिकी खेलों में होने वाले टैटिकल टाइमआउट जैसे थे। फुटबॉल प्रेमियों का आरोप था कि इससे खेल की लय टूटी है। दूसरी तरफ कमर्शियल मौके बनते देखे गए। यह पहले से तय था कि अनावश्यक दखलंदाजी के लिये चर्चित अमेरिकी राष्ट्रपति का दखल भी इस टूर्नामेंट में दिखेगा, क्योंकि इस आयोजन के मुख्य टूर्नामेंट अमेरिका में खेले जा रहे थे। इस आयोजन के दौरान तब विवाद सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को दिखाए गए रेड कार्ड की समीक्षा करने को कहा था। विवाद तब उठना शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन पर से एक मैच का बैन हटा लिया गया, जिसके बाद बालोगुन ने राउंड-ऑफ-16 का मैच खेला। लेकिन इस अभूतपूर्व दखल के बाद दंभी अमेरिका टूर्नामेंट से बाहर होने से नहीं बच पाया। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो के साथ पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने के लिये मैदान पर आए तो लोगों ने अपनी भड़ास निकालते हुए खूब हट्टिंग की। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आयोजन के दौरान जो खामियां सामने आईं, आने वाले विश्वकप में फीफा उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा।

जंतर-मंतर आंदोलन का अंत का मध्यांतर



● राकेश अचल

सिस्टम के खिलाफ जंतर-मंतर पर खड़े हुए काकरोचों का आंदोलन बिना नतीजा समाप्त हो गया. सवाल ये है कि ये इस असंगठित, प्रायोजित आंदोलन का मध्यांतर है या अंत ? काकरोचों के आंदोलन के हीरो सोनम वांग्चुक ने जिस तरीके से जेपी नट्टा के आश्वासन के बाद अपना आमरण अनशन समाप्त करने का ऐलान किया है, इससे उन आरोपों की आंशिक पुष्टि हो गई है कि ये आंदोलन प्रायोजित था और युवाओं के गुस्से की हवा निकालने के लिए किया गया था. हमारे बुदेलखंड में ही क्या पूरी हिंदी पट्टी में एक कहावत है - ' हलुआ मिला न मांडे, दोऊ दीन से गए पांडे '. मैं इस कहावत को अब यूँ कहना चाहता हूँ कि -'रबड़ी मिली न चमचम, दोनों दीन से गए सोनम'.ये इसलिए क्योंकि नीट की नाकामियों के खलनायक केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और न सरकार काकरोचों के प्रति संवेदनशील बनी रही. संसद मार्च के लिए बढ रहे काकरोचों को पुलिस ने जमकर धुना.

भारत के जेन-जी के साथ ये दूसरा छल है. पहली बार छलिया अन्ना हजारे थे, इस बार ये भूमिका सोनम वांग्चुक ने शानदार ढंग से निभाई.सोनम युवाओं की आशाओं के प्रतीक बन गए थे. वे युवाओं को प्रभावित करने वाले देश के दूसरे नेता हैं. पहले नायक राहुल गांधी हैं. उनके पास राजनीति दल भी है, लेकिन सोनम के पास कुछ नहीं है.

मैं सोनम वांग्चुक का बहुत सम्मान करता हूँ. अभी भी इसमें कोई कमी नहीं आई है. बावजूद इसके मुझे लगता है कि सोनम वांग्चुक दूसरी बार गच्चा खा गए. पहली बार तब चार महीने जेल में रखने के बाद सरकार ने उन्हें अचानक रिहाकर लद्दाख के लाखों लोगों की उम्मीद के आंदोलन को समाप्त कर दिया. वे कुछ हासिल नहीं कर पाए.

सोनम को दूसरा गच्चा जंतर-मंतर पर मिला. वे किसी लाट साहब के कहने पर काकरोचों के मंच पर आए थे. उन्होंने 2० दिन का आमरण अनशन किया और उस आदमी के आश्वासन पर तोड़ दिया जो उस मंडली का हिस्सा है जो जन विरोधी है, फासिस्ट है अशिष्ट है.

काकरोच लड़ाई हारे लेकिन मुझे खुशी है कि उनकी एकजुटता की वजह से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन देश की सड़कों को जाग्रत किया. संसद को डराया. मुझे लगता है कि कोकरोची आंदोलन के दमन के बावजूद ये आंदोलन का अंत नहीं बल्कि मध्यांतर ही माना जाएगा. ऐसे आंदोलन और खड़े होंगे भले ही उनमें सोनम वांग्चुक जैसे लोग न हों. निश्चित रूप से यदि सोनम वांग्चुक धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे तक रुक जाते तो इस कामयाबी का सेहरा उनके सिर बंधता. लेकिन वे नाकाम रहे इसलिए अब नाकामी का सेहरा भी उन्ही के माथे पर बंधेगा. देश के प्रधानमंत्री ने संसद के मानसून सत्र से ठीक कुछ घंटे पहले जिस ठंग से अपने संदेश में युवाओं का मजाक बनाया उससे जाहिर है कि वे तो नहीं सुधरने वाले नहीं हैं. उन्हें जनता ही आम चुनवा में सुधार सकती है.



सिने जगत

'द प्राइड ऑफ भारत' के लिए इंटरनेशनल एक्शन टीम तैयार



फिल्म निमाता सदीप सिंह अपनी आने वाली बड़ी ऐतिहासिक फिल्म ह्रद प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराजह्व के बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में ऋषभ शेट्टी, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब इस फिल्म की और ख़ास बनाने के लिए निमाताओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक्शन टीम को शामिल किया है, जो फिल्म के युद्ध और एक्शन सीन्स को शानदार बनाने पर काम करेगी।

इस पीरियड फिल्म को भव्य बनाने के लिए जो टीम जोड़ी गई है वह फिल्म के युद्ध और एक्शन सीन्स को तैयार करने में जुट गई है। लोकप्रिय सीरीज ह्वाम ऑफ थ्रोन्सह्व के अलावा ह्ववाईर्कंसह्व, ह्रद विचरह्व और ऑस्कर विनर फिल्म ह्वग्रीविटोह्व में अपने एक्शन डिजाइन के लिए पहचाने जाने वाले मार्क हेंसन इसके एक्शन की कमान संभालेंगे।

फिल्म की एक्शन टीम में हॉलीवुड के दो और अनुभवी नाम भी शामिल किए गए हैं। पहले व्लाद रामिबर्ग, जिन्होंने ह्रद फेट ऑफ द प्यूरियसह्व, ह्रब्लंडशॉर्टह्व और ह्रलुसिफरह्व जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है, दूसरे क्रैग मैके, जो ह्रट्रॉय: फॉल ऑफ ए सिटीह्व के लिए चर्चित रहे हैं। मेकर्स का दावा है कि यह टीम भारतीय ऐतिहासिक सिनेमा के सबसे बड़े युद्ध सीन्स में से एक तैयार करेगी।

सबसे प्रेरणादायक योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनके जीवन पर अब तक फिल्म और टेलीविजन में 6० से अधिक प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। इसकी शुरुआत 1923 में आई मूक फिल्म सिंहगढ़ से हुई थी। मेकर्स का कहना है किह्रद प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति..... इस ऐतिहासिक विरासत को नए पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचाएगा।

लंदन में लड़खड़ाए अक्षय कुमार, गिरते-गिरते बचे

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार रिवार को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान नजर आए। इन्हें दौरान उनका नया सफेद दाढ़ी वाला लुक चर्चा में रहा। उन्होंने सफेद और बेज रंग की ड्रेस के साथ काले बालों वाला नया लुक अपनाया था। स्टैडियम में अक्षय कुमार के साथ सैफ अली खान और तैमूर हंसने लगे। अक्षय ने भी इस पल को मजाकिया अंदाज में लिया और सभी साथ में हंसते हुए आगे बढ़ गए।अक्षय कुमार और सैफ अली खान जल्द ही फिल्म 'हैवान' में साथ दिखाई देंगे। यह फिल्म 11 सितंबर 2०26 को रिलीज होने वाली है। दोनों करीब 18 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। इससे पहले वे 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'ये दिलवाली', 'आरजू' और 2००8 में रिलीज हुई 'टशन' में साथ काम कर चुके हैं।

काँकरोच जनता पार्टी (उखड) का र्संसद चलो़र आह्वान केवल एक विरोध मार्च नहीं, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक राजनीतिक रणनीति है। खासकर जिस तरह से इस आंदोलन को छात्र आंदोलन का स्वरूप दिलावाया जा चुका है, वह डीप स्टेट के इशारे पर बनी विपक्ष की शांतिर सरकार घेरो रणनीति का कमाल भी करार दिया जा रहा है। देखा जाए तो संसद के मानसून सत्र के दौरान गत 2० जुलाई को जंतर-मंतर से संसद की बाढ़ें भरकर करने के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे और कूच किया, वह बिल्कुल संगठित राजनीतिक आंदोलन के तर्ज पर हुआ।

मजे की बात तो यह कि संसद के निकट पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो पूर्व प्रायोजित झड़प हुई और उसके बाद हालात निर्वाचित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, इससे यह संसद मार्च राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबारों के दफ्तरों में इससे जुड़े कई नीतिगत सवालों पर भी बहस होने लगी। सोशल मीडिया पर जवाह सरकार विरोधी भड़काऊ वीडियो वायरल होने लगे, वहीं सत्ताधारी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों की कारगुजारियों के वीडियो साझा कर दिए, जिससे लोगों की सहानुभूति पुलिस और सरकार के साथ बनी रही।

यदि संसद मार्च के घटनाक्रमों पर संतुलित नजर डालें तो यही प्रतीत होता है कि जब बड़ी संख्या में सीजेपी (उखड) समर्थक र्संसद चलो़र मार्च के लिए जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़े, तो भले ही उनकी मुख्य मांगें शिक्षा सुधार, परीक्षा-पत्र लीक और जवाबदेही था, लेकिन इरादे तोड़फोड़ वाले और खतरनाक थे, अन्यथा पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना पड़ता। यूँकि संसद के मानसून सत्र के दौरान माननीयों की सुरक्षा के दृष्टिगत

दिल्ली पुलिस ने व्यापक बैरिकेडिंग की थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोका, हिरासत में लिया तथा कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा उपद्रव करने के बाद आंसू गैस और बल प्रयोग की घटनाएं सामने आईं। इससे अफरातफरी मच गई।

देखा जाए तो इस आंदोलन की प्रमुख मांगों में नीट (उपखड) पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं पर कार्यवाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की जवाबदेही, कुछ नेसओं द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, आंदोलन से जुड़े लोगों के साथ संवाद आदि हैं, लेकिन जो उत्पात दिखाई-सुनाई दिया, वह विपक्षी संस्कार नहीं तो क्या है ? फिर भी, केंद्र सरकार ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से बातचीत की पहल भी की, जो टकराव के बीच संवाद की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नट्टा ने सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर उखड प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और मांगपत्र ग्रहण किया। बावजूद इसके आंदोलनकारी अपनी मांगों पर कायम हैं। सवाल है कि संसद मार्च के क्रम में जो कुछ गड़बड़ हुआ, क्या वह लोकतांत्रिक है, सही था या गलत ? तो जवाब होगा कि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र का वैध हिस्सा है। वहीं, सरकार द्वारा आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप कदम है। फिर भी संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारी की ओर से कुछ-कुछ गलत हुआ जो अनुचित लगा। यदि प्रदर्शनकारियों ने निषिद्ध क्षेत्र में संबरन प्रवेश कर या बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तो वह कानून-

व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा। वहीं, यदि पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया या शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक कार्रवाई हुई, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि, इस पर अलग-अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं और सभी तथ्यों के गोलमोल जवाब ही मिले हैं, जिनपर एतबार करना मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसका अंतिम सत्यापन अभी होना बाकी है, कई अनरक कहानियां गूढ़ रहे हैं। इससे सरकार संसत में है और विपक्ष तरह-तरह के आरोप लगाकर सिस्टम की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोकतांत्रिक समाधान का सर्वोत्तम रास्ता संवाद है। लेकिन इस मुद्दे गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं।

यही वजह है कि राजनीतिक दृष्टि से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं:- पहला, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दबाव की राजनीति। दूसरा, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा अर्थथ्यियों के असंतोष को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास। तीसरा, विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का अवसर और चौथा, सरकार के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आंदोलनकारियों से संवाद की चुनौती आदि। एक, युवा असंतोष का राजनीतिक रूपांतरण: बेरोजगारी, परीक्षा-पत्र लीक, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर नाराजगी को संगठित करने का प्रयास दिखाई देता है। दो, डिजिटल से सड़क तक: सोशल मीडिया पर शुरू हुआ अभियान अब वास्तविक जन-प्रदर्शन में बदलता दिख रहा है, जो यह संकेत देता है कि ऑनलाइन असंतोष भी राजनीतिक दबाव का माध्यम बन सकता है।

तीन, सरकार पर दबाव: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन मार्च का

समय चुनना सरकार और संसद का ध्यान आकर्षित करने की रणनीति माना जा सकता है। सरकार और उखड प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने की खबर भी इसी दबाव का संकेत है।

चार, विपक्ष के लिए अवसर: यदि विपक्ष इस असंतोष को राजनीतिक समर्थन देता है, तो यह सरकार को घेरने का एक नया मुद्दा बन सकता है। वहीं यदि आंदोलन स्वतंत्र बना रहता है, तो यह पारंपरिक दलों से अलग एक नई राजनीतिक शैली का संकेत होगा।

पांच, प्रतीकों की राजनीति: रश्कोंकरोचर जैसे अपमानजनक शब्द को पहचान और प्रतिरोध के प्रतीक में बदलना राजनीतिक संचार की एक प्रभावी रणनीति है। जो विशेषकर युवाओं के बीच ध्यान आकर्षित करती है। छठा, उखड की कई मांगें और उसकी प्रस्तुति व्यंग्य एवं प्रतीकात्मक राजनीति का हिस्सा हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि यह एक स्थायी राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बन जाएगी। दरअसल उसका वास्तविक राजनीतिक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वह सोशल मीडिया की लोकप्रियता को लंबे समय तक संगठित जनसमर्थन और ठोस राजनीतिक संगठन में बदल पाती है। निष्कर्षतः यही कहना उपयुक्त होगा कि लोकतंत्र में न तो हिंसक टकराव समाधान है और न ही वैध असंतोष को केवल बल पूर्वक दबाना। लिहाजा सबसे उचित रास्ता यही है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, कानून का सम्मान हो, और सरकार ठोस संवाद के माध्यम से शिक्षा सुधार तथा परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों का विश्वसनीय समाधान प्रस्तुत करे। अन्यथा छात्र आंदोलन यदि राष्ट्रीय स्वरूप अक्षिवाक्य का लेगा तो न्यायतनी सत्ता को लेने के देने पड़ जायेंगे।

सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

सोनभद्र, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नवीन व्यवस्था अन्तर्गत सी0एम0 डैशबोर्ड के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन विभागों को शासन द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह उसका शत-प्रतिशत निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें, पी0एम0 सूर्य घर योजना की समीक्षा की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि पी0एम0 सूर्य घर योजना के अन्तर्गत बैंक के माध्यम से सब्सिडी आदि की सुविधा बैंक के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाये उन्होंने एल0डी0एम0 को निर्दिशित करते हुए कहा कि



पी0एम0 सूर्य घर योजना को अन्तर्गत जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये है उसका सत प्रतिशत

निस्तारण बैंकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये। श्री गौड़ ने मुख्यमंत्री युवा

उद्यमी लोन योजना के भी प्रगति की समीक्षा की और उपायुक्त उद्योग एवं एल0डी0एम0 को निर्दिशित

करते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभार्थियों के पत्रावलियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये, समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए करते हुए कहा कि विकास कार्यों, लाभार्थीपरक व जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे कार्यों के प्रगति में तेजी लायी जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को पत्राचार करना सुनिश्चित किया जायेगा। बैठक के दौरान उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधूरे निर्माण कार्यों को तीव्र गति से पूर्ण कराने की

कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतपाल वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनन्द पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक जय राम सिंह, डी0सी0 मनरेगा रवीन्द्र वीर सिंह, अपर जिला सभा सभा अधिकारी विनय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 एस0के0 राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहे।

वृक्षारोपण अभियान के तहत एनसीएल ने एक दिन में 3 लाख से अधिक किया पौधारोपण



सिंगरौली, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में कोल इंडिया के वृहद् वृक्षारोपण अभियान के तहत सिंगरौली स्थित मिनीरब कोयला कंपनी नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक ही दिन में 3 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता एवं हरित भविष्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया। यह अभियान एनसीएल की सभी 10 उत्पादन इकाइयों के लीज क्षेत्र के साथ-साथ लीज क्षेत्र के बाहर स्थित वन प्रभागों में भी संचालित किया गया।

120 हेक्टेयर क्षेत्र में चलाए गए इस विशाल वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत अर्जुन, पीपल, महुआ, शीशम, हल्दू, करीदा, आँवला, नीम, झली, जामुन, आम, अमरुद, अमलतास,

लेमन ग्रास, पलाश, गुलमोहर, टेकोमा, बेर, शहतूत, चिरायता, सेमल, सतावर, बकैन आदि सहित स्थानीय जलवायु एवं पारिस्थितिकी के अनुकूल विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस अभियान में परिधि्व समुदाय से जुड़े लोगों सहित 950 से अधिक लोगों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। यह पहल 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत प्रकृति संरक्षण एवं जलवायु संवर्धन के प्रति एनसीएल की सशक्त भागीदारी को रेखांकित करती है। साथ ही, यह भावी पीढ़ियों के लिए हरित विरासत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान भी है। गौरतलब है कि एनसीएल सतत खनन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का निरंतर निर्वहन कर रही है।

सिंचाई विभाग नहर निर्माण के लिए कर रहा कौड़ियों के भाव

विस्थापितों की तर्ज पर पुनर्वास पैकेज व अन्य सुविधाओं की मांग

दुदही (सोनभद्र), 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। कनहर बांध अमवार से निकलने वाली नहर के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की जमीनों का बैनामा कराने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन विभाग द्वारा तय की गई मुआवजा राशि को लेकर क्षेत्र के किसानों में गहरा असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग उनकी कमीती जमीनों को कृषि दर पर लेकर कौड़ियों के भाव अधिग्रहित कर रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा नहर के लिए जमीन अधिग्रहण की दर मात्र 11 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है। आज के समय में जमीन की बाजार दर (मार्केट वैल्यू) इससे कहीं अधिक है। किसानों का कहना है कि इस मामूली रकम से वे भविष्य में अपने परिवार

के लिए दूसरी जमीन भी नहीं खरीद पाएंगे। कम मुआवजे के कारण किसानों के सामने अपनी आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने सिंचाई विभाग की इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किसानों का कहना है कि जब कनहर बांध के मुख्य विस्थापितों को सरकार द्वारा तीन पीढ़ियों तक का 7 लाख 11 हजार रुपए पुनर्वास पैकेज और अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो नहर निर्माण के लिए जमीन देने वाले किसानों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? नहर के प्रभावित किसान हीरालाल, उमेश, रामलाल, सूरज सहित तमाम किसानों ने भी मांग की है कि उन्हें मुख्य विस्थापितों की तर्ज पर ही सम्मानजनक मुआवजा और पुनर्वास पैकेज दिया जाए।

इस संबंध सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन के आदेशानुसार नहर के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण की जा रही है।

एक ऐसा महाविद्यालय जहाँ 7 विषयों के अध्यापक ही नही, कैसे होगी इन विषयों की पढ़ाई

(रमेश यादव) दुदही, सोनभद्र, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। दुदही शुरू से ही शिक्षा के प्रति सजग रही है।आजादी से पहले ही दुदही में सरदार रुप चंद सिंह जी के नेतृत्व में 1946 में ही गवर्मेन्ट हाई स्कूल की स्थापना हुई थी विकास की ओर उन्मुख होते हुए वर्ष के 1965-66 में राजकीय इंटर कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 1973 में आजादी के लगभग 25 वर्ष बाद ही दुदही तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय दुदही जिला मिजार्पु की स्थापना हुई।शुरूआत में भले ही दुदही में शिक्षा सहित अन्य संस्थान बेहतरीन ढंग से संचालित हुए हों लेकिन वर्तमान में प्राचार्य सहित मात्र 11 प्रोफेसरों के भरोसे राजकीय महाविद्यालय दुदही के लगभग 2000 छात्र/छात्राओं का भविष्य देखने को मिल रहा है। महाविद्यालय में स्नातक में कला, वाणिज्य तथा गणित व विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला वर्ग में हिंदी, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में मात्र एक विषय वनस्पति विज्ञान से कक्षाएं संचालित है, परन्तु प्राध्यापकों के अभाव



में आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी उबड़ खाबड़ पठारी भू भागों में स्थित यह महाविद्यालय अपने क्षेत्र के छात्रों के उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कराने में असफल साबित हो रही है क्योंकि महाविद्यालय में 25 प्राध्यापक के पद सृजित है, जिसमें मात्र 11 कार्यरत हैं। महाविद्यालय में महत्वपूर्ण विषयों अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित विषयों के पद रिक्त चल रहे हैं जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय है यह महाविद्यालय कई उतार चढ़ाव और उपेक्षाओं को झेलते हुए अपने स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण कर चुका है जो दुदही क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। अपने स्वर्ण जयंती वर्ष पूर्ण करने वाले जिले का अग्रणी महाविद्यालय को भले ही आज

10 साल से जलभराव की समस्या, अंतरराज्यीय बस स्टैंड बेहाल

सिंगरौली, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। जिला मुख्यालय स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड वैदून के मुख्य प्रवेश द्वार पर जलभराव की समस्या वर्षों बाद भी खत्म नहीं होसकी है।स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 10 वर्षों से बारिश के दौरान यहां पानी भरने की समस्या बनी हुई है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार को जोड़ने वाले इस प्रमुख बस स्टैंड से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है। बारिश के समय मुख्य द्वार पर पानी भरने और परिसर में बने गड्ढों के कारण बसों एवं अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है।इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। व्यापारियों का कहना है कि मस्जिद तिराहा, तुलसी मार्ग और काली मंदिर क्षेत्र का बारिश का पानी बस स्टैंड परिसर से होकर चौपाटी की ओर निकलता है।हाल ही में बनाई गई नाली भी लकसी में प्रभावी साबित नहीं हो रही है।उनका आरोप है कि नाली का निर्माण पर्याप्त चौड़ाई और गहराई के बिना किया गया, जिसके कारण पानी जमा हो जाता है। व्यापारियों ने बताया कि बस स्टैंड के समीप दुर्गा मंदिर के सामने अतिक्रमण हटाने के बाद फल मंडी संचालन को योजना बनाई गई थी।

अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, मचा हड़कंप

60.79 बल्क लीटर मदिरा जप्त, तीन आरोपियों पर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज

सिंगरौली, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। जिले में अवैध शराब के संग्रहण एवं बिक्री के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर गोवर बैनल के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सतीश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने वृत्त सखई क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त की है।

कार्रवाई के दौरान ग्राम गौड़बहरा में आरोपी कैलाश यादव की किराना दुकान एवं रियायशी मकान की तलाशी ली गई। यहाँ से 50 नग देशी मदिरा प्लेन, 50 नग देशी मदिरा मसाला तथा 48 नग ली माउंट 6000 बीयर केन सहित कुल 42 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 15 हजार 576 रुपये बताई गई है। इसी प्रकार ग्राम पुरेल एवं पठरीदा में आरोपी रामजी जायसवाल एवं रामनरेश बेस की किराना दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 34 नग देशी मदिरा प्लेन, 2 नग देशी मदिरा मसाला, 2 नग गोवा मदिरा, 3 नग ली माउंट बीयर बोतल एवं 20 नग बीयर केन सहित कुल 18.79 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई। इसकी अनुमानित कीमत 6 हजार 370 रुपये है।

आबकारी विभाग द्वारा दोनों कार्रवाइयों में कुल 60.79 बल्क लीटर अवैध मदिरा, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 21 हजार 946 रुपये है, जब्त की गई। तीनों आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी



अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक सुशी नीलिमा मार्कों, आबकारी आरक्षक बहादुर सिंह, अनुज भुजिया एवं रीतिका चैकसे सहित विभागीय अमला शामिल रहा।

खाद, प्लाईऐश परिवहन और अवैध खनन पर कड़ी निगरानी के निर्देश



सिंगरौली, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय-सीमा बैठक में कलेक्टर श्री गोवर बैनल ने जिले में संचालित विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को डबल लॉक उर्वरक गोदामों का नियमित एवं औचक निरीक्षण कर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद एवं बीज की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। प्लाईऐश परिवहन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खनिज विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं परिवहन विभाग को संयुक्त जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले

वाहनों पर जल्ती एवं जुर्माने की कार्रवाई करने को कहा। साथ ही अवैधरत खनन एवं भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने वृक्षारोपण अभियान को गति देने, राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, नक्शा सुधार अभियान और वनाधिकार दावों के पुनः परीक्षण के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। सीएम हेल्थलाइन की समीक्षा करते हुए एंी कलेक्टर ने लैबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा जनसुनवाई एवं लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में अपर कलेक्टर पीएस जिपाठी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

ट्रक-ट्रेलरों के आतंक से तीर्थ यात्री परेशान
सिंगरौली, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। स्थानीय शक्ति पीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर, शक्ति नगर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक एवं आस्था का केंद्र है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों से वर्ष भर श्रद्धालु एवं तीर्थयात्री दर्शन-पूजन के लिए यहां आते हैं। आगामी श्रावण मास को देखते हुए प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। मंदिर के सामने स्थित प्राचीन मार्ग के समीप एनटीपीसी सिंगरौली तृतीय चरण विस्तार परियोजना द्वारा निर्माण कार्य हेतु बनाए गए मॉटेरियल यार्ड के कारण क्षेत्र में भारी वाहनों, ट्रकों, ट्रेलरों एवं बल्क कैरियरों का आवागमन लगातार बढ़ गया है। आरोप है कि ये भारी वाहन मंदिर परिसर के पार्किंग स्थल में खड़े कर दिए जाते हैं तथा मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर पार्किंग में खड़े वाहनों के चालक खुले आम मांस एवं मदिरा का सेवन करते हैं, जिससे धार्मिक स्थल की गरिमा भी प्रभावित हो रही है। इस संबंध में मंदिर के तीर्थ पुरोहित पंडित वेदांती मिश्रा द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के उपरांत स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पार्किंग से वाहनों को हटवाया था, किंतु परियोजना प्रबंधन की आगरवाही के कारण पुनः भारी वाहन मंदिर परिसर एवं पार्किंग क्षेत्र में खड़े किए जाने लगे हैं। मंदिर के तीर्थ पुरोहितों एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने परियोजना प्रबंधन से पूर्व में निर्मित, किंतु वर्तमान में बंद पड़े वैकल्पिक मार्ग को पुनः चालू करने का आग्रह किया था, ताकि निर्माण कार्य में लगे भारी वाहनों का आवागमन उसी मार्ग से हो सके और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सके। इसके बावजूद अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। वर्तमान स्थिति में मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग एवं प्राचीन मार्ग पर लगातार भारी वाहनों की आवाजाही तथा मंदिर पार्किंग में ट्रक-ट्रेलरों के खड़े रहने से श्रद्धालुओं, महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी हुई है।

एसडीओपी कार्यालय के पास कोयले से लदा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला

सिंगरौली, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में सोमवार को एसडीओपी देवसर कार्यालय के पास कोयले से लदा एक भारी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक सड़क किनारे लगी तार की बाड़झी और कई पेड़ों को तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। गंभीरत रही कि घटना के समय आसपास कोई राहगीर या अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक तेज गति में था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जियावन थाना क्षेत्र से पुरे दिन ओवरलोड कोयले से लदे भारी वाहन गुजरते हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने और नियमित जांच अभियान चलाने की मांग की है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। चालक की स्थिति और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है।

डीएम की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु/एमओयू क्रियान्वयन बैठक सम्पन्न



गाजीपुर, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। जिला उद्योग बन्धु /एम0ओयू0 क्रियान्वयन की बैठकअपराह्न 5.00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार गाजीपुर में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया। बैठक में बशिष्ठ यादव, मे0 बाई प्लास्ट, मुगलानेचक, गाजीपुर विद्युत बिल में रेगुलरटी सरचार्ज के सम्बन्ध में कमेटी बनाकर जांच कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में व्यापारियों ने सीवर लाइन हेतु खोदे गये गड्ढों के कारण खराब हुई सड़कों को दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि नगर पालिका परिषद् के अन्दर सड़कों एवं सी0सी0 रोडों के निर्माण हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी को जांच करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय। ए0के0 दुबे, गाजीपुर ने अनुरोध किया था कि मुगलानीचक में मेरा निजी भूखण्ड है, जिसमें औद्योगिक इकाई स्थापित किया जाना है, जिसके सम्बन्ध शिवाजी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर द्वारा बताया गया कि 80 प्रतिशत नाले का निर्माण हो चुका है। रमेश कुमार आर्य, नन्दगंज, गाजीपुर द्वारा औद्योगिक आस्थान नन्दगंज, गाजीपुर के परिसर में साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, पुलिस चौकी/पुलिस भ्रमण की व्यवस्था किये जाने की मांग की गई थी। जिसके सम्बन्ध में स्ट्रीट लाइट लग गयी है। पुलिस चौकी हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया गया।

करीमुद्दीनपुर पुलिस द्वारा दो वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

गाजीपुर, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के द्वारा चलाये जा रहे अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान मे गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मु०बाद जनपद गाजीपुर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक राज नारायन अपने हमराह हे०का० हरिमोहन सिंह, रि०का० कृष्ण कुमार पटेल, रि०आ० प्रसाद प्रशान्त कुमार गणेश वाहन सरकारी मय चालक का० बलराम गोड व उ०नि० कमलेश गुला, का० मंगला प्रसाद, रि०का० वीरेन्द्र पाल मय वाहन सरकारी जीप मय चालक का० भीम भारती दिनांक 20.07.2026 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अस० 109/26 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित अभियुक्त 1. संतोष चौहान पुत्र स्व० गुलाब चौहान 2. किशन डोम पुत्र अमरजीत डोम निवासीगण ग्राम लहूडीह थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को ग्रीनीफिल्ड रोड पड़ाव से प्रभारी निरीक्षक राज नरायन मय हमराह हे०का० हरिमोहन सिंह, रि०का० कृष्ण कुमार पटेल, रि०आ० प्रसाद प्रशान्त कुमार गणेश वाहन सरकारी मय चालक का० बलराम गोड व उ०नि० कमलेश गुला, का० मंगला प्रसाद, रि०का० वीरेन्द्र पाल मय वाहन सरकारी जीप मय चालक का० भीम भारती द्वारा समय 22.00 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार गिरफ्तार कर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया।

खेत बचाओ अभियान के तहत यूबीआई गहमर ने लगाया कैम्प

गाजीपुर, 21 जुलाई (देवव्रत संवाद)। युनियन बैंक ऑफ इंडिया, गहमर शाखा में ह्रद्यखेत बचाओ अभियान-2026ह्रद्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गाजीपुर राजदेव कुमार, शाखा प्रबंधक नहमर, कुतुबपुर एवं पकड़ित सहित बैंक के बीसी एवं सीएफएल स्टाफ उपस्थित रहे। बैठक में अधिक से अधिक सार्वजनिक एवं ग्रामीण नागरिकों को उपरोक्त योजनाओं का लाभ दिलाने, किसान क्रेडिट कार्ड बनाने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। अग्रणी जिला प्रबंधक ने सभी अधिकारियों एवं बीसी को गांव-गांव जाकर जनजागरूकता अभियान चलाने तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए।

